THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) Yes, Sir.

(b) These recommendations relate to expanding the definition of Migrant Workman, defining responsibility of the Principal Employer and the Contractor, making penalities more stringent, permitting third parties to file claims, transfer of claim cases to native States of the workmen and provision for special courts/summary trials.

(c) These recommendations have been examined by the Govt. in consultation with the Ministry of Law and the matter is being processed further.

Establishments Registered under the Inter-State Migrant Workmen Act, 1979

2493. SHRI G. PRATHAPA REDDY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the numbers of establishments which have been registered under the Inter-State migrant workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979;

(b) the number of cases of violations of this Act which came to notice during the last three years; and

(c) what panal action was taken against the guilty?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Delay in Settlement of Provident Fund Accounts

2494. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the difficulties of employees in getting their accounts settled with various Regional Provident Fund Commissioners;

(b) if so, what steps are being taken to reduce red-tape and bureaucratic delays in settlement of dues in Provident Fund Commissioners offices;

(c) number of people employed by this Department in Andhra Pradesh; and

(d) what specific measures have been taken to streamline working of Provident Fund Office in Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (d) According to the EPF Organisation, there is no undue delay/difficulties in settlement of PF claims of the EPF subscribers. However, for providing prompt service to the subscribers, a massive computerisation process has been launched in the Organisation including its PF Office in Andhra Pradesh. As on 31-3-1993, the number of staff employed by the Organisation in Andhra Pradesh was 1190.

श्रम कानूनों में संशोधन करने के लिए मजदूर संघों के साथ परामर्श

2495. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम कानूनों, विशेषकर औद्योगिक विवाद, अधिनियम, 1947 तथा व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में मजदूर संघों के साथ परामर्श किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन पर मजदूर संघों की प्रतिक्रिया कैसी रही है; और

(ग) अधिनियमों के प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषतायें क्या हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) अप्रैल, 1990 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में नए औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के लिए विशिष्ट प्रस्तावों को प्रारूपित करने के लिए मई, 1990 में श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में नियोजक संगठनों तथा केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन के प्रतिनिधियों को लेकर एक द्विपक्षीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अक्तूबर, 1990 में अपनी रिपोर्ट दे दी। इसकी सिफारिशों पर सर्वसम्मति नहीं व्यक्त की गई। फरवरी, 1992 में आयोजित राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में, जुलाई, 1992 में आयोजित स्थायी श्रम समिति में और सितम्बर, 1992 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया। केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठन, स्थायी श्रम समिति तथा भारतीय श्रम सम्मेलन के सदस्य हैं। रिपोर्ट के असहमति वाले विषयों पर भी पांच राज्यों के श्रम मंत्रियों की समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया। इन विचार-विमर्शों के आधार पर और औद्योगिक पुनर्संरचना सम्बन्धी अन्तर्मन्त्रालयीन दल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए भी व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने से संबंधित विशिष्ट प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।